

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, November 25, 1981/
Agrahayana 4, 1903 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock

[MR. SPEAKER in the Chair.]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Report of Backward Class Commission

*41. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) when the Backward Class Commission headed by Shri Mandal submitted its report to the Government of India;

(b) the reason for the delay in placing it before the Parliament; and

(c) when is it proposed to be laid now?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c). The Backward Classes Commission headed by Shri B. P. Mandal submitted its Report to the President of India on 31.12.1980. The Report is under examination of the Government and it will be placed before the Parliament together with the Memorandum of action taken, as provided for, under Article 340(3) of the Constitution.

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: The Government has willfully evaded answering the substantive part of my question.

My question (b) is the reason for the delay in placing it before the Parliament. From the reply it has been

revealed that almost one year has passed. In the last session when we raised this issue before this House through a Notice of Adjournment Motion, you yourself expressed apprehensions about the attitude of the Government in not placing it before Parliament.

(Interruptions)

एक माननीय सदस्य : श्री गण.
श्री गण... इन्होंने ही नाम दिया था—
“ब्राह्मण राम, शूद्रा राम”

... (व्यवधान) ...

MR. SPEAKER: Order, please.

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: The Minister of State for Home Affairs Mr. Venkatasubbaiah assured this august House that the Government would be placing the report before Parliament in the last session itself, whatever might be the pressure of other work. May I ask what has prevented the Government and who has prevented the Government from placing the report before Parliament in the last session itself? I would like to know how much time the Government would take to study the report and then place it before Parliament and when it would be implemented. I would like to have a specific answer with specific dates.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: It is incorrect to say that I have not replied to it. In my reply, I have specifically mentioned that the report is under examination of the Government and that it would be placed before Parliament together with the Memorandum of Action taken.

He wanted to know about my colleague's statement which was made during the last session of Parliament.

While making the statement before the House, my colleague himself gave the reasons why it had not been possible to lay the report on the Table of the House.

The report is under examination of the Government. It is a big volume and we have to consult the various Ministries also because unless we receive all the reports from the various Ministries, it is not possible to examine it.

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Again the Government is trying to avoid an answer. This shows the anti-backward classes attitude of this Government. When this report was submitted before the Government at a function attended by the Prime Minister, the speech of the Prime Minister at that function itself had showed that the Government was trying to confuse the issue. The Prime Minister said there at that meeting that there was a question whether this backward-class issue should be decided through social backwardness or economic backwardness and that speech of the Prime Minister itself was an indication that the Prime Minister and her Government are against the backward classes who are socially and educationally backward in this country. So, I would like to know if it is not a fact that the anti-reservation agitation in Gujarat against reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been instigated by the Gujarat Government with the blessings of the Central Government, only to avoid the issue of the reservation of the backward classes and to avoid implementing the Backward Classes Commission report.

THE PRIME MINISTER (SHRI-MATI INDIRA GANDHI): I refute the allegations that he has made against me and the Central Government.

श्री मनोराम बागड़ी : इस सवाल पर झगड़ा चाहते हो, क्या ? स्पष्ट जवाब दो.... (ब्यवधान)

सत्यजित महोदय : जवाब दे रहे हैं।

श्री मनोराम बागड़ी : हम को इस सवाल पर उत्तेजित कर रहे हैं। फूल लगा कर गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, वह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?

... (ब्यवधान) ...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : पिछली बार जब सदन में ऐसा ही झगड़ा हुआ था तब इन्होंने कहा कि हम अगले सेशन में रखेंगे। अब जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? स्पष्ट शब्दों में बताएं कि रिपोर्ट रखेंगे या नहीं?

श्री जयपाल सिंह : यह टॉल पापुलेशन के 52 प्रतिशत का सवाल है...

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The question itself is without any basis, and he has made a baseless allegation because when the Report was submitted, it was not the Prime Minister but the Home Minister who made the speech.

(Interruptions)

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: No. It was the Prime Minister who did it. (Interruptions)

श्री राम लाल राही : गृह मंत्री जी कहें कि पहले हम ने गलतबयानी की थी।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Stating that the Government is interested in creating an anti-reservation agitation itself shows that the Member is making a baseless allegation, and he has no reason for making such an allegation. As I have said already, we are going to place the Report on the Table of the House after examining it, together with the Memorandum of Action Taken.

श्री मनोराम बागड़ी : कब ?

... (ब्यवधान) ...

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : स्पीकर साहब, बैकवर्ड क्लासेज की रिपोर्ट के

सम्बन्ध में मेम्बर साहबान को जो जज्बात है मैं उन की कद्र करता हूँ और यह सच्चाई है कि पहले काका कालेलकर साहब को बैकवर्ड क्लासेज के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आई थी, उस पर कुछ भी नहीं हुआ।

अब मेम्बर साहबान को इस बात की जिज्ञासा है कि यह रिपोर्ट भी न दबा दी जाए... (व्यवधान)... आप जरा शास्त्रि से सुनिए। आप बहुत दानिशमन्त इन्सान हैं। बुरा लगता है जब इस तरह से करते हैं। लोग सोचते हैं कि आप क्या करते हैं। उस की वजह से मेम्बर साहबान, पर्टीकुलरली जो बैकवर्ड क्लासेज से सम्बन्ध रखते हैं या बैकवर्ड क्लासेज के साथ हमदर्दी रखते हैं, वे यह समझते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को भी उसी तरह से समाप्त कर दे। मैं आप को, यह यकीन दिलाता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को बहुत सेरियसली स्टडी किया है और वह स्टडी कर रही है लेकिन इस रिपोर्ट का सम्बन्ध भारत सरकार की तत्काल मिनिस्ट्रीज से और हिन्दुस्तान की तमाम प्रान्तीय सरकारों से है। उनके साथ कन्सल्टेशन कर के फालो-अप एक्शन जो है, वह रिपोर्ट के साथ ही रखा जाता है। कांस्टीट्यूशन के मुताबिक रिपोर्ट के साथ अगर फालो-अप एक्शन नहीं रखते हैं, तो बात अधूरी रहती है। इसलिए हम मेमोरेण्डम तैयार कर रहे हैं। प्रान्तीय सरकारों से भी कन्सल्ट करेंगे और मिनिस्ट्रीज से भी कन्सल्ट कर रहे हैं और जितनी जल्दी ही सकेगा हम इस हाउस के सामने रिपोर्ट रखेंगे और तब हम यह बात सकेंगे कि इस रिपोर्ट की रिफरेंस से से कौन सी बातें हैं जो नामुमकिन हैं, वे पूरी नहीं की जा सकती और कौन कौन सी बातें हैं जो पूरी की जा सकती हैं। फिर

मेम्बर साहबान को खुला टाइम मिलेगा और वे अपने विचार दे सकेंगे। उस पर उनकी राय आ जाएगी। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि जितनी एंजवाइटी आप को है, उतनी ही हम को भी है और जो चीजें बैकवर्ड क्लासेज के सम्बन्ध में सरकार को करनी चाहिए वे तुरन्त की जाएँ, उन में देर न की जाए, मगर जो पासीबिल हो सकता है, वही किया जा सकता है। जितनी देर सरकार है, उतनी देर लगनी ही चाहिए और बात सोच-समझ कर करनी चाहिए। सब से सलाह-मशविरा कर के, डेमोक्रेटिक तरीके से सारी रस्में पूरी कर के, डेफनीट बात कह सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तसल्ली रखें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कितना समय लगेगा सोचने और समझने में, यह आप बताइए।

... (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : पहले बता तो दिया है। यह आप क्या कर रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी।

श्री मनीराम बागड़ी : गृह मंत्री जी ने जो बात कही, वह खुली जवान से कही। यह बात सही है कि हर काम शासन के सारे अंगों से होते हैं और समझ से भी होते हैं। यह सवाल सिर्फ बैकवर्ड क्लासेज का नहीं है बल्कि समूचे देश का है और समूचे देश की इकाइयों से जुड़ा हुआ है। मैं गृह मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि जो बात डेफनीट नहीं होती है, पक्की बात नहीं होती है, वह हवाई बात होती है। आप झूटा गढ़ें कि फवां तारीख तक रपट सबन में रख दी जाएगी और यह बात नहीं होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी रखी जाएगी क्योंकि 100 साल में भी जल्दी है, आप की 50 पृष्ठों के बाद भी जल्दी

है, आप की सरकार चली जाएगी, तब भी जल्दी है और आप नहीं रहेंगे तब भी जल्दी है। आप पक्का खूंटो गाड़ें कि सरकार फलां तारीख तक यह रपट रख देगी ?

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब बागड़ी जो खुद जानते हैं कि 'जल्दी' का मतलब यह नहीं होता कि साल निकल जाएंगे। वे 100 साल की बात करते हैं और उन का यह भी ख्याल है कि हमारी दूसरी पुस्त इस को ला कर रखेगी। यह बात गलत बात है। डेट न मुकर्रर करने का कारण सिर्फ यही है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हिन्दुस्तान के, उन सब के साथ इस का ताल्लुक है और प्रान्तीय सरकारें अपनी पॉजिशन देख कर अपने अपने विचार इस पर दें।

श्री मनोराम बागड़ी : यह सब देखना सरकार का काम है। आप जबाब 'हां' या 'ना' में दें। कोई निश्चित तारीख बताएं, जिस तक सरकार इस को रखेगी। आप बताएं कि फलां तारीख तक इस को रख देंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इन को निश्चित तारीख बतानी ही पड़ेगी।

श्री जैल सिंह : एक बात जो रिज-नेविल होती है, उस को करने के बाद भी अनरीजनेविल बना देते हैं। यह बात रीजनेविल है कि जल्दी होनी चाहिए लेकिन तारीख मुकर्रर करनी पड़ेगी, यह रीजनेविल बात नहीं है।

श्री मनी राम बागड़ी : आप कोई तारीख निश्चित कीजिए कि फलां तारीख तक वह रख दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : मैं निश्चित तारीख बताने की स्थिति में नहीं हूँ। (व्यवधान) वह रिपोर्ट फोलों अप एक्शन के साथ रखी जाएगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बारी बारी से बुला रहा हूँ। आप को भी बुलाया। अब उनकी बारी है। अब आप बैठिये। श्री उत्तम राठौर।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप हम लोगों को मौका नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं रिकार्ड निकाल कर दिखा दूँ तो फिर आप ऐसा नहीं कहेंगे। श्री उत्तम राठौर।

श्री बौलत राम सारण : यह क्या तरीका है? आप जो शोर मचाते हैं, उन को मौका देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब क्या यह है कि आप भी शोर मचाएं ?
I have not called you Mr. Saran. I have called Shri Uttam Rathod. I am not going to allow you, Mr. Saran. Please sit down. This is my discretion and I am using it.

श्री उत्तम राठौर : अध्यक्ष महोदय; जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बताया कि काका कालेलकर ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस की वजह से बैकवर्ड क्लासिज के लोग

काफी परेशान हैं। अभी मंडल कमीशन ने रिपोर्ट पेश की। जिस के बारे में पिछले सेशन में दो बार सवाल उठाया गया और आखिर के जवाब में श्री वेंकटसुब्बय्या ने कहा था कि प्रिटिंग की डिफिकल्टी की वजह से रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की जा सकती। उसको लगभग 11 महीने हो चुके हैं। गवर्नमेंट को और कितना समय लगेगा इसको पेश करने में या इस पर एक्शन लेने में? इस चीज पर फैसला लेने में आप कितना समय और लेंगे और कब तक इस कम्युनिटी को आप फायदा दे सकेंगे?

श्री योगन्द्र मकवाना : बार बार यह बताया गया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा इसे पेश किया जायेगा। **व्यवधान**

श्री मनी राम बागड़ी : यह कोई जिम्मेदारी की बात है?

अध्यक्ष महोदय : आप टेन्टेटिवली कोई वक्त दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री जयपाल सिंह कश्चप : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार हम को यह आश्वासन दिया गया था कि यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कांचिन में भी पत्रकारों की सभा में यह आश्वासन दिया था। मैं यह प्रश्न गृह राज्य मंत्री जी से फिर से पूछना चाहता हूँ क्योंकि गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री के वक्तव्यों में भेज कर कन्ट्राडिक्शन हो जाता है। जहाँ तक हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लोगों का मामला है यह कोई ऐसी ही बात नहीं है, यह बहुत जिम्मेदारी का मापला है। मैं गृह राज्य मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या वे जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के (4) में बैकवर्ड क्लासिज का क्रोइटेरिया निर्धारित किया गया है कि सोशलली और एजुकेशनली वीक हों, क्या इस क्रोइटेरिया को बदलने की बात की जा रही है क्योंकि कई बार बाहर ऐसी बातें कही गयी हैं। बिना संविधान में संशोधन के ऐसा नहीं हो सकता। क्या सरकार इकानामिक, सोशल, एजुकेशनल बैकवर्डनेस का क्रोइटेरिया

बदलने का विचार कर रही है? क्या सरकार इसलिए इस रिपोर्ट को इतने समय तक छपाई में रखना चाहती है कि चुनाव आ जाए और 2-4 महीने पहले यह रिपोर्ट प्रस्तुत करके बैकवर्ड क्लासेज का ध्यान इसकी ओर खींचा जाए और इस बात का प्रचार किया जाए कि हम उन के लिए कुछ करने जा रहे हैं और उनसे वोट प्राप्त किए जाएं। क्या सरकार इसको चुनाव का माध्यम बनाना चाहती है? तीसरी बात यह है कि

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है, एक प्रश्न कीजिए। **(व्यवधान)**

श्री जयपाल सिंह कश्यप : हर स्टेट में बैकवर्ड क्लास **(व्यवधान)** . . . सरकार को इसको एडाप्ट करने में क्या दिक्कत हो रही है। उस लिस्ट को एडाप्ट कर के उस के मुताबिक संविधान में जो व्यवस्था है, उस को लागू कर के सरकार मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में देर क्यों कर रही है? हम लोग स्पेसिफिक तारीख चाहते हैं जो सदन को बताई जाए, क्योंकि देश के करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री योगन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 340 इससे संबंधित हैं। आर्टिकल 340 के सब सेक्शन 3 में क्लियरली लिखा है—

“The President shall cause a copy of the Report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.”

तो ले तो हम कर रहे हैं और जहाँ तक आर्टिकल 64 का ताल्लुक है, इस क्रोइटेरिया को चेंज करने के हक में हम नहीं हैं।

(व्यवधान)

SHRI HARIKESH BAHADUR: Sir, in the previous Session there was a statement by the Minister of State for Home Affairs that he would place the Report before the House in that Session itself, but on the last day he changed it and said that it would be placed sometime after. But now what is the

main difficulty before the Government in placing it in this Session?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, there is no difficulty. As I said Government will place the Report on the Table of the House but we have also to place the memorandum of action taken. Now, for the memorandum of action taken we have to examine the report and the examination of the Report takes time. So, no specific date can be given. (Interruptions)

श्री रामाक्षर शास्त्री: अध्यक्ष जी, इस में अनावश्यक विलंब तो हो ही रहा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पिछड़ा वर्ग आयोग के किसी मंबर ने रिपोर्ट के बारे में नोट आफ डीसेंट दिया है और अगर दिया है तो नोट आफ डीसेंट का ब्यौरा क्या है? उस के बारे में सरकार का क्या कहना है?

श्री योगेन्द्र मकवाना: जब रिपोर्ट को टेबल पर रखा जाएगा तो उस में सब आ जाएगा। आज मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।

श्री रामाक्षर शास्त्री: जवाब नहीं दिया गया है। आप इस चीज को बताएं। इस से हम समझेंगे कि आपकी नीयत क्या है। अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय: जवाब दे दिया है क्या?]

श्री योगेन्द्र मकवाना: जवाब दे दिया है कि हम अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। रिपोर्ट रखने वाले हैं। जब रखेंगे तब वह इस को भी देख लेंगे। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री रशीद मसूद।

Whatever is being spoken without my permission will not form part of the record.

श्री रशीद मसूद: गढ़वाल में इलैक्शन को प्रेशर में आ कर पोस्टपोन कर दिया गया है। तारीख आपने तय की थी लेकिन उस तारीख को नहीं करवाया। कहीं यह मामला

भी ऐसा ही तो नहीं है? इस के ऊपर तमाम बैंकवर्ड लोग, पिछड़े हुए लोग और वे लोग जो बैंकवर्ड क्लासिस के साथ हमदर्दी रखते हैं; एजीटेडिड हैं। क्या रिपोर्ट को टेबल पर न रखने की वजह यह तो नहीं है कि इस के पीछे उन लोगों का प्रेशर है जिन्होंने एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट गुजरात में चलाई थी?

[श्री रशीद मसूद: कुश्वाल में]

अध्यक्ष को परेशान करने के लिए आपने यह किया है - तारीख को नहीं रखी है, लेकिन इस तारीख को नहीं करवाया - कहीं यह मामला भी ऐसा ही तो नहीं है, उस के ऊपर तमाम बैंकवर्ड लोग, पिछड़े हुए लोग और वे लोग जो बैंकवर्ड क्लासिस के साथ हमदर्दी रखते हैं; एजीटेडिड हैं - कहीं यह मामला भी ऐसा ही तो नहीं है, उस के ऊपर तमाम बैंकवर्ड लोग, पिछड़े हुए लोग और वे लोग जो बैंकवर्ड क्लासिस के साथ हमदर्दी रखते हैं - कहा (रिजर्वेशन को नहीं देकर) कि वजह यह तो नहीं है कि इस के पीछे उन लोगों का प्रेशर है जिन्होंने एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट गुजरात में चलाई थी -

श्री योगेन्द्र मकवाना: ऐसे किसी प्रेशर का सवाल ही नहीं उठता है। (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद: हम प्रोटेस्ट में वाक आउट करते हैं।

[श्री रशीद मसूद: हम प्रोटेस्ट

में वाक आउट करते हैं -]

(Some hon. Members then left the House)

(At this stage, Shri Mani Ram Bagri, Shri Ram Lal Rahi and some other Members came and sat on the floor of the House near the Table.)

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, what are they doing?

(Interruptions)

SHRI RAJESH PILOT: Sir, we must stop this kind of behaviour of the Opposition in the House.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, I do not think this is the way....

(Interruptions)

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Sir, is it unjust to demand that a categorical date should be announced as to when this report would be placed on the Table? Is it unjust on behalf of the Opposition Members to demand a categorical date? Is it unjust? Is it undemocratic? *(Interruptions)* Why are they refusing to give the date? The Prime Minister is here. She can announce the date. At least the feeling must be assuaged. It is a long delayed thing and people outside are feeling very bitterly and they have got an impression that there are vested interests who are preventing this report from being discussed here. I want the Prime Minister to give an assurance.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I want to ask a question. Do you support this kind of behaviour in the House? Is this the meaning of a united Opposition? That is the question I want to ask.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: If you give the assurance, then....

(Interruptions)

SHRIMATI INDIRA GANDHI: It is a specific question. Do you support this kind of behaviour or not?

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Will you please listen to me? There are rules.

(Interruptions)

SHRI SAMAR MUKHERJEE: They have sought your protection that some categorical time should be announced. *(Interruptions)*. First of all, you must realise that this is rigid attitude of the Government. *(Interruptions)*

SHRIMATI INDIRA GANDHI: This is the planned strategy of the Opposition. It is not on this question alone. It is on every question.

(Interruptions)

SHRI SAMAR MUKHERJEE: It is the deliberate decision of the Government not to place the report on the Table of the House. This is your planning, not the planning of the Opposition. You have decided not to have any discussion here on this very report. *(Interruptions)* Here you are raising the question of behaviour. Your party should behave and you should give a categorical assurance.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing is going on record; they are saying all this without my permission.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, I do not think you need a speaker here... May I ask you one question: Do you need a Speaker or not?

I have seen it for the last.... I do not know whether there might be something that we should not function according to the established practices of this House. The opposition may have a point, and they have their own, but we can sort it out in a better way. There are always means by which discussions can be had in private and here also, and we can sort out things very amicably and in a very happy manner, but if this type of thing goes on and on, I think we are cutting at the very root of democracy which you proclaim to defend. I will ask both the sides to cooperate in a certain manner. This does not behave the Members. I will ask the hon. Minister also to have a dialogue with the Opposition and sort out things. There is nothing much to be agitated about so much like this.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I do not approve of this. This is what I have said.

This is going to cut at the very root of what you are trying to defend.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: But then you can discuss it. You show an attitude of agitation, all right, but if you cross the limits certain times, then it will not lead to anything. It will be self-defeating.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: It is not good.

(Interruptions)

SHRI SATISH AGARWAL: Mr. Speaker, Sir, you are very well aware of the norms that we have adopted for our party. So you should not blame the entire Opposition. I do not associate myself with dharna and all that.

I have got one humble suggestion to make. May I know whether the Government can commit itself to place the Report on the table of the House on 16th of February when we meet for the Budget Session?

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I can allow half-an-hour discussion on it if you like.

SHRI SATISH AGARWAL: Half-an-hour discussion will not solve the problem. They should give a firm date—16th of February, month of March or April or say even during the Budget Session, Are you in a position to say something during the Budget Session?

SHRI S. B. P. PATTABHI RAMA RAO: Sir, I may make a submission. The Hon. Minister has made it clear that it not only concerns his own various departments, but he has to get replies from various States. How can the Home Minister give a date when he does not know by what time the States will send the reply?

(Interruptions)

SHRI SATISH AGARWAL: Then let the Home Minister say that it is not possible to lay it till 1985.

(Interruptions)

SHRI INDRAJIT GUPTA: Sir, we can understand that the Hon. Members are very agitated at the delay and it does not mean that because all of us are sitting here, we are satisfied with everything that the Government does in the House. There are many things with which we are not at all satisfied. We are not at all satisfied with the Government's reply. But the point is that this is question Hour. For more than 45 minutes various Members on this side have been asking substantially the same question. There is no different question. It is one question—Why is the Government not laying it and when will it lay? And for 45 minutes the same reply is given from the Government side.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: And they asked the same question.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I, therefore, feel that after you have heard repetitions of the same question and the repetition of the same reply, situation need not have been allowed to escalate to this stage. Now the Hon. Minister, Mr. Makwana has said that if they have to lay the Report, they have also to lay the Memorandum of Action Taken and he has implied that for preparation of the Memorandum he has to get the replies and materials from the States, and therefore it is delayed. I want to make a suggestion. In view of what is happening here, is it not possible to lay the copy of the Report on the Table of the House? I do not know why any delay is required for that. The Memorandum of Action Taken can come later on. The Members are asking for the Report to be laid on the Table of the House. What is the difficulty? The Memorandum of Action Taken can come later.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I may explain the position. Under Article 340 of the Constitution it is specifically mentioned:

"The President shall cause a copy of the Report so prescribed, together with a Memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament."

Now it is a Constitutional provision. How can it be waived?

SHRI INDRAJIT GUPTA: In that case it means that during Question Hour on this question if things are allowed to escalate to this stage, there is a complete deadlock. These Hon. Members and many people here and many people outside want to see the Report. The Report should be made public and the Minister is saying that there is a Constitutional provision. It is not said in the Constitutional Provision that heavens will fall if the Memorandum of Action Taken is given after 15 days. What will happen?

(Interruptions)

SHRI INDRAJIT GUPTA: After all, the Memorandum of Action Taken will be on the basis of the Report only; not on the basis of anything else. There should be some response from that side after all.

SHRI K. LAKKAPPA: Why don't you condemn the behaviour of the Hon. Members?

SHRI INDRAJIT GUPTA: I will condemn their behaviour, but I will condemn your obstinate attitude also. If I were not condemning them, I would also sit here with them. That is not the point. We don't want it. After all this is a very important question, but there are other questions also. This is Question Hour, I am emphasizing that this is Question Hour. What about all the Members whose other questions are there? Therefore, I would request you; as the hon. Speaker and custodian of the House you should take some initiative to intervene in this matter. You are just allowing the same question and the same answer to go on for almost 40, 45 minutes. You must guide the House.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: That is what I said. We can have a dialogue outside, and in my Chamber also and sort things out. Not like this.

PROF. MADHU DANDAVATE: May I quote a precedent? I would like to quote a precedent.

SHRI INDRAJIT GUPTA: The hon. Prime Minister could have said something much earlier. Now I suppose it is too late, because there is a different mood now. If she had said something much earlier in the proceedings, I think this matter could have been sorted out. (Interruptions). No, no; she got up to say something, but the ebullient Mr. Lakkappa prevented her from saying something. (Interruption) Yes; that is what was going on. She got up to say something, but he interrupted and prevented her from saying that. (Interruptions) No. I have to protest against that also.

SHRI K. LAKKAPPA: You cannot convert the Question Hour into a debating society here. (Interruptions). Question Hour is a Question Hour.

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, I would like to quote a precedent. The legitimate difficulty of the Government and the Treasury Benches seems to be that the Action Report is to be prepared, and that is the reason why there is delay. I will quote a precedent which can help find a way out. You can find it in the proceedings of the Lok Sabha.

In the 5th Lok Sabha, when the Bharagava Commission's report was not laid on the Table of the House, I myself demanded that, I moved a privilege motion, and then it was admitted that there was a delay. You know that in the case of a number of Reports—it is mentioned in the concerned Act, for instance the MRTTP Act and the Commission of Enquiries Act—from the time the Report is submitted to Government, it has to be presented to Parliament within six months.

I agree that Article 340(3) does not have such a provision. He is right. But I will quote a precedent. When the Bhargava Commission's report was laid on the Table of the House.

(Interruptions)

SHRI K. LAKKAPPA: This is too much. Under what rule, are you allowing him? He is converting the Question Hour into something else; can he talk anything and everything? He is disrupting the Question Hour.

(Interruptions)

PROF. MADHU DANDAVATE: I am speaking with your permission, Sir. . .

SHRI K. LAKKAPPA: He might have taken your permission, Sir, but. . .

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, when I have taken your permission, I don't need his permission.

(Interruptions)

I was only trying to find a way out. When the Bhargava Commission's report was submitted to this very House in the 5th Lok Sabha, a No Action report was submitted, in my opinion. According to him, there was an Action Report. What was the Action Report? The report said that since there are various facts of the report that had to be gone through, they would require some time to go into the technical aspects of the problem; and, therefore, no decision could be taken on the report at that stage. I got up in the House and asked him how can an inaction report be described as an Action report. And Sir, fortunately or unfortunately that is left to you; I do not want to cast any aspersion on your predecessor—the Speaker gave the ruling that even if the Government says: "At this stage we cannot move in the matter; we require more time", even that will be treated as an Action Report. Taking clue from this, they can come forward with the Report; and about the Action Taken Report, they can say they require more time, and find out the difficulty. If the Report is laid on the Table of the House, both the Houses will be satisfied. That is the way-out.

MR. SPEAKER: That is why I had been saying that we should sit and sort it out.

PROF. MADHU DANDAVATE: I have quoted the precedent.

श्री. जैल सिंह: आनरेबल स्पीकर साहब, मैं इतनी विनती करता हूँ कि इस तरह से हाउस की डिगनिटी कायम नहीं रहती। प्रो० वण्डवते जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त जी बड़े दूरन्देज पार्लियामेंट-रियन हैं, उन्होंने ने समझाया बुझाया लेकिन मुझे नजर आता है वे हमको समझा रहे हैं अपने साथियों को नहीं समझा रहे हैं। (व्यवधान) सभी हम से कहते हैं कि नीची नजर रख कर चला करों लेकिन इन से कोई नहीं कहता कि उरिया होके न निकले। (व्यवधान) अगर हमारी बात सुनी है तो पहले हाउस में आर्डर करो। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Now I appeal to you to sit down.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: In the Bhargava Commission Report, there was no constitutional provision to lay it on the Table of the House with the memorandum of action taken.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I cannot have a discussion here; we can have a discussion and sort this thing out later on.

(Interruptions)

SHRI INDRAJIT GUPTA: Where do you want to have a discussion in your Chamber?

MR. SPEAKER: About sorting out this problem.

AN HON. MEMBER: You extend the Question Hour.

SHRI INDRAJIT GUPTA: This has to be talked about with a little bit of flexibility. What can I do?

(Interruptions)

SHRI SATISH AGARWAL: You cannot be firm like that.

MR. SPEAKER: I have to bring about that. Now you please take your seat.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: We shall talk about it.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please go to your seats.

(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND ENVIRONMENT (SHRI C. P. N. SINGH): He is having a personal talk and is casting aspersion on the Prime Minister without the permission of the Chair and has been carrying on and on.

SHRI K. LAKKAPPA: He is not in his seat; he has no right to speak. He cannot speak from here; it should not go on record. Nobody should speak without the permission of the Chair-

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Order please.

(Interruptions)

श्री मनोराम बागड़ी: अध्यक्ष जी, हाउस के लीडर का जरा ध्यान हो जाएगा ...

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Why don't you sit down?

SHRI C. P. N. SINGH: He cannot talk like this.

(Interruptions)

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I am on a point of order. Can a Minister threaten the Speaker?

(Interruptions)

MR. SPEAKER: What are you doing now?

(Interruptions)

Foreign elements in Khalistan Activities

*42. SHRI G. Y. KRISHNAN:
SHRI M. RAM GOPAL REDDY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have made efforts in connection with the movement for Khalistan to find out if there is any foreign element behind it;

(b) whether some arrests have been made in this regard;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a): Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise.

(d) Intelligence has been strengthened in this regard by the State and Union Government agencies.

SHRI G. Y. KRISHNAN : This Khalistan movement is neither in the national spirit nor towards any love or brotherhood or fraternity but is only a result of factionist and extremist elements. I want to know whether the Government is considering this movement as anti-national and secondly, in answer to part (a) of my question, as to 'whether the Government have made efforts in connection with the movement for Khalistan to find out if there is any foreign element behind it' has been answered affirmatively. Who is that foreign power and what steps have been taken by the Government? Who is that foreign agency?

गृह मंत्री (श्री जल सिंह): स्पिकर साहब, जहाँ तक खालिस्तान की मूवमेंट का सवाल है, इस के सम्बन्ध में ऐसे हाउड्स हैं कि कहीं कुछ विदेशी सत्ता इस में कोई सहायता करती है, लेकिन इस को डेफिनिट कहना मुश्किल है। एक बात साफ है कि कुछ देशों के सिटिजन, जो पहले हमारे थे, लेकिन बाद में बाहर जा कर वहाँ की सिटिजनशिप